नए शहर बसाने में निजी निवेशकों के लिए दरवाजे खोलेगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

आवास मंत्री ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की समीक्षा

देहरादून। प्रदेश में नए शहरों को बसाने के लिए सरकार निजी निवेशकों के लिए दरवाजे खोलने जा रही है। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनके लिए सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को आवास विभाग के अंतर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित करने को लेकर मंत्री अग्रवाल ने बैठक की। बैठक में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य प्रशासक प्रकाश चन्द्र दुम्का ने आवास विभाग के अंतर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें मुख्य रूप से निजी निवेश में आने वाली चुनौतियों व उसके निवारण के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन और प्रोत्साहन राशि पर चर्चा की गई।

आवास मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान नीतियों में संशोधन किया जाए। साथ ही निवेश अनुकूल नीति तैयार की जाए, जिसमें निजी निवेशक राज्य में विभिन्न टाउनशिप योजनाओं में निवेश कर सकें। उन्होंने ने कहा कि ये भी देखा जाए कि निवेशकों को प्रोत्साहन राशि कैसे दी जा सकती है।

मकसद ये है कि राज्य में निवेश के प्रति आकर्षण बढ़े। उस पर अन्य राज्यों की प्रोत्साहन नीतियों का अध्ययन कर स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। निजी निवेश को भूमि क्रय भू-उपयोग परिवर्तन और मानचित्र स्वीकृत और इसके साथ-साथ अन्य विभागों से मिलने वाली सेवाओं को सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से निश्चित समय के अंतर्गत प्रदान करने का तंत्र विकसित किया जाए।

जिससे निजी निवेशकों को आवश्यक विभागीय सहयोग तेजी से मिल सके। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में निजी निवेश विभिन्न परियोजनाओं में विशेषकर टाउनशिप आधारित परियोजनाओं में निजी निवेशक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वातावरण देना जरूरी है। जिससे राज्य में निवेश के माध्यम से आवश्यक रोजगार सृजन किया जा सके। इसके साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते हुए कर संग्रह में वृद्धि की जा सके।

प्रस्तावित नए शहरों के विकास में निजी निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके लिए नए शहरों के विकास को प्रस्ताव के साथ-साथ निजी निवेश को आकर्षित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव आवास सुरेंद्र नारायण पांडेय, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जितेंद्र त्यागी, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मोहन सिंह बर्निया, सचिव हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण उत्तम सिंह चौहान आदि मौजूद थे।